

लेक्चरर को प्रमोशन के बजाय डिमोशन करके वापस वरिष्ठ शिक्षक बनाया?

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस विवादित आदेश पर स्टे देते हुए इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को रखी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेक्चरर को प्रमोशन देने के बजाय डिमोशन किए जाने के विवादित आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता लेक्चरर श्रवण लाल खोखार ने रेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, जहां 8 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान तत्कालीन चेयरपर्सन विकास सीतारामजी भाले व सदस्य चेतनराम देवड़ा ने उसे स्टे देते हुए अंतरिम राहत

■ हाईकोर्ट ने रेट के रजिस्ट्रार को भी अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि ट्रिब्यूनल ने पहले तो उसे अंतरिम राहत दी, परंतु बाद में आदेश बदल दिया गया

दी थी, परंतु बाद में इस आदेश को बदल दिया गया। जब यह मामला ट्रिब्यूनल में सूचीबद्ध ही नहीं थी, उसी दौरान इस प्रकरण में दूसरा आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी कर दिया गया, जो कि गैरकानूनी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत पैरवी के लिए पेश हुए थे। प्रकरण की सुनवाई

के दौरान न्यायाधीश रवि चिराणिया ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को 6 मार्च 2026 को शपथपत्र देकर जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। जिस पर 27 मार्च को रेट की ओर से शपथ पत्र के साथ जवाब पेश हुआ था। इस जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को होने वाली सुनवाई

पर रजिस्ट्रार को पेश होने के आदेश दिए थे। मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता श्रवण लाल खोखार वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2015 में इनका तबादला करते हुए उदयपुर से अजमेर लगा दिया गया था। वर्ष 2016-27 को डीपीसी में पदोन्नति मिली और उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2025 की डीपीसी में उन्हें उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी जानी थी, परंतु उसे वापस वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड-2 के पद पर ही लगा दिया। साथ ही वर्ष 2016 में लेक्चरर पद पर किया गया प्रमोशन भी रद्द कर दिया।

ऐसे में इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस रवि चिराणिया की एकलपीठ ने कहा कि, जब ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के संबंध में 8 अगस्त 2025 को आदेश पारित किए, तब उसकी सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में 17 जून 2025 को याचिकाकर्ता के डिमोशन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए इस प्रकरण की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है। साथ ही इस सुनवाई पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

रोडवेज कर्मचारी 16 अप्रैल को जयपुर में दंगे प्रदेशस्तरीय धरना

जयपुर। एटक-एआईटीयूसी से जुड़ी राजस्थान स्टेट रोडवेज एंजलाइज यूनियन के आ न पर गुरुवार, 16 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जयपुर स्थित रोडवेज मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। इस महाधरने में सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही वर्गों के कर्मचारी भाग लेकर अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव के अनुसार यह आंदोलन लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। जिससे रोडवेज संचालन और कर्मचारियों की कार्य स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। धरने में शामिल होने से पहले कर्मचारी जयपुर आगार से रैली के रूप में रवाना होकर रोडवेज मुख्यालय पहुंचेंगे। यूनियन ने सभी कर्मचारियों से अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले हिस्ट्रीशीटर की तलाश

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। शहर के मालवीय नगर थाना इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का शांतिर हिस्ट्रीशीटर निकला है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल गुर्जर ग्वालियर के सरसपुरा गांव (बिजौली) का निवासी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती और मारपीट के कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी टीम फिलहाल ग्वालियर में डेरा डाले हुए है और लगातार दबिश दे रही है। गौरतलब है कि 25 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी बीच सड़क पर एक गर्भवती महिला के पास पीछे से पहुंचकर उससे छेड़छाड़ करता दिखाई दिया। महिला के

■ वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर का शांतिर हिस्ट्रीशीटर है।

विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। पीड़िता ने भी घटना की सूचना पुलिस को दी थी। हालांकि, प्रारंभिक स्तर पर लापरवाही बरतने के आरोप में जवाहर सर्किल थाना के एसएसआई महेश चंद्र और हेड कांस्टेबल अंगद राम मीणा को लंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों ने आरोपी को पकड़ने के बाद बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था।

मुख्यमंत्री ने किया छात्राओं के साथ वर्चुअल संवाद

मुख्यमंत्री ने छात्राओं के अनुभव सुने, आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान

जयपुर (कांस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी अब निर्णय लेने की मुख्य भूमिका भी निभाएगी। इससे महिलाएं योजना एवं बजट बनाने सहित देश के हर अहम निर्णय में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों का दृढ़ आत्मविश्वास ही विकास के सपने को हकीकत में बदलेगा। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे थे।

■ प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं, इससे संसद-विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा : भजनलाल शर्मा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। छात्राएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही समाज और प्रदेश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दृढ़ आत्मविश्वास के जरिए पूरे

देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी के कार्यों को महिला शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से जुड़ी मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस सहित विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की छात्राओं से संवाद कर उनके कार्यक्षेत्र की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सुझावों को सुना। शर्मा ने पचपटवार के केमिकल इंजीनियर श्रेया के

चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र के चयन की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। ऑस्ट्रेलिया में डेटा साइंस की छात्रा तात्सवी ने मुख्यमंत्री को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सलेंस योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मेगैस गैल्स कॉलेज की छात्रा नय्या ने कहा कि इस अधिनियम ने महिलाओं को नीति निर्माण में सशक्त भागीदारी का मौका दिया है। कार्यक्रम में छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

खरीफ-2025 में अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाई

■ सरकार की इस राहत से 5.57 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फैक्स-लेम्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई, 2026 अथवा सरकार लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2026 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जयपुर सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 5.57 लाख किसानों पर बकाया लगभग 2184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता। सहकारिता मंत्री ने किसानों से इस विस्तारित अवधि का लाभ प्राप्त करते हुए ऋणों का चुकाया कर शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

सुखियां बटोरने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे अशोक गहलोत : दिलावर

राज्य सरकार नियम-क़ानून के तहत शीघ्र चुनाव के पक्ष में है : शिक्षा मंत्री

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं और बचकानी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून एवं न्यायालयों का सम्मान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सिफारिशों की अनुपालना के पक्षत ही चुनाव करवाये जाने के लिए निर्देशित किया है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उसका विस्तृत अध्ययन करेगी एवं विधिवेत्ताओं से राय लेकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शीघ्र चुनाव संपन्न करवाएगी।

■ दिलावर ने कहा "100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" वाली कहावत चरितार्थ कर रहे गहलोत

■ होटलों में चली पिछली सरकार वाला दौर था कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन : दिलावर

दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने तो 13 साल तक चुनाव कराए ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाने रखने के लिए 1975 में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे हम पर न्यायालय की अवहेलना करने और कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन के आरोप लगा कर सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।

मदन दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घर पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के सम्मान को तार-तार करने का काम किया था। अपने ही सहयोगी को नाकारा निकम्मा मक्कार जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था। वे अपने अपराधों का दोष एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर थोपकर एक घोर अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी कोई नहीं है। अशोक गहलोत जी के जैसा राज्यपाल का असम्मान करने वाला कोई नहीं है। और अनगलं टिप्पणियां कर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

26 साल पुराने मालपुरा सांप्रदायिक दंगा मामले के 10 आरोपी दोषमुक्त

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष कोर्ट ने करीब 26 साल पहले 10 जुलाई, 2000 को मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों में चार जनों के मामले में दस आरोपियों को संदेह लाभ में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल रज्जक, साजिद अली, फहीम अहमद, ईशाक, अब्दुल वाहिद, रकीब अहमद, मुनीर, रऊफ व नवाब को दोषमुक्त किया है। इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही हो गए थे और आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास साबित नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों के अधिवक्ता वाहिद नकवी ने बताया कि आरोपियों की

■ 10 जुलाई 2000 को मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों में चार जनों की हत्या का मामला

■ इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही हो गए थे और आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास साबित नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

शिनाख्त नहीं हो पाई थी और जेल से पहले ही पुलिस थाने में उनकी पहचान उजागर हो गई थी। जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित थी, उनके खिलाफ नई साक्ष्य ही पेश नहीं हो पाई थी। जिन हथियारों से हत्या होने का दावा किया गया था, उन पर खून ही नहीं था। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास का आरोप साबित ही नहीं कर सके। वहीं ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही भी हो गए। इसके चलते ही कोर्ट ने दस आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गौरतलब है कि जुलाई 2000 को परिवारिया मंजू देवी ने मालपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जीप में जाते समय उन पर हमला हुआ। इस हमले में 3 जनों की मौत हुई और दो लोग घायल हो गए।

संजीव नैन ने बताया कि मानसरोवर में 'कांसेप्ट आरएनए' कोिंगफ संस्थान की चौथी मंजिल पर संचालित 'हॉट हाउस ट्रीट कैफे लाउंडज' में खाने-पीने की आड में युवाओं को

स्कूल के खेल मैदान की भूमि का आवंटन रद्द करने पर रोक

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के बाजौर स्थित सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित की गई भूमि का आवंटन रद्द करने वाले स्थानीय कलेक्टर के गत 5 फरवरी के आदेश को क्रियावित्त पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्थानीय कलेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूल समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता केतन धाभाई ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2023 में स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल विकास समिति के साथ बैठक का हवाला देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा कि यह जमीन स्कूल से चार सौ मीटर दूर स्थित है। जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस पत्र के आधार पर कलेक्टर ने गत पांच फरवरी को इस भूमि का आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन बदले

■ सीकर के बाजौर स्थित सरकारी स्कूल का मामला

■ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्थानीय कलेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूल समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

में दूसरी जमीन आवंटित नहीं की। याचिका में कहा गया कि आवंटन रद्द करने के अल्प समय बाद ही इस जमीन को मैसर्स बाजोर डेजेंट सफारी एंड रिसोर्ट्स को आवंटित कर दी। याचिका में कहा गया कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल के खेल मैदान का आवंटन रद्द किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आवंटन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सहकार मसाला मेले की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर (कांस)। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) द्वारा जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' का आयोजन होगा। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में मेले की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-



सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मसाला मेले की तैयारियों पर चर्चा की।

■ जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक होगा आयोजन

निर्देश प्रदान किए। शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन सहकारिता विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह मेला अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन चुका है, जिसका जयपुरवासियों को बेसरी से इंतजार रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले को आनन्दुक्त ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी आवश्यक

व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। मेले में फुटफॉल बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सुलना ही, मेले में ऑर्गेनिक उत्पादों व श्रीअन्न उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने मेले में स्टॉल्स की संख्या में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि मेले में नवाचारों का भी व्यापक रूप से समावेश किया जाए, जिससे लोगों का मेले के प्रति आकर्षण बढ़े। उन्होंने मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शन एवं विक्री के लिए देश-प्रदेश से आने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास व परिवहन सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

सफाई सेवा मैराथन शुरू करेगा निगम

जयपुर। नगर निगम जयपुर की स्वच्छता रैकिंग में सुधार लाने के साथ सफाई में बेहतर कार्य करने के लिए योजना बना रहा है। इसी दिशा में निगम शनिवार से विशेष सफाई अभियान चलाएगा। सफाई सेवा मैराथन के आगाज के साथ हर अधिकारी जयपुर को स्वच्छ-सुंदर बनाने के लिए फील्ड में काम करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर सफाई के प्रति सजगता बरतने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सफाई कार्यों को लेकर मोटिवेट किया और बैठक में अधिकारियों को सफाई में जयपुर को अक्वल बनाने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने को कहा। निगम आयुक्त ने सफाई सेवा मैराथन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। निगम आयुक्त ने बैठक में कहा कि हर अधिकारी-कर्मचारी का एक ही लक्ष्य स्वच्छ जयपुर सुंदर जयपुर होना चाहिए। सफाई कार्य को लेकर अब सीएसआई की भी रैकिंग तय होगी। प्रथम, दूसरे और तीसरे नम्बर पर रहने वाले सीएसआई को स्वच्छता हीरो के सम्मान से नवाजा जाएगा।

मानसरोवर-श्याम नगर में हुक्का बार पर छापा

पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार कर 17 लोगों के चालान काटे

जयपुर। गुलाबी नगरी में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बुधवार को सख्त कार्रवाई करते हुए मानसरोवर और श्याम नगर थाना क्षेत्रों में तीन स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 संचालकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हुक्का पीते पाए गए 17 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान किए गए।



अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने मौके से संचालक प्रकाश वासवानी को गिरफ्तार कर 10 हुक्के और तंबाकू फ्लेवर जब्त किए। इसके अलावा न्यू आतिश मार्केट स्थित 'हुक्का क्लब' पर कार्रवाई करते हुए मैनेजर

हनुमान (निवासी खैरथल) को गिरफ्तार किया गया और वहां से भी हुक्का सामग्री बरामद की गई। वहीं श्याम नगर थाना पुलिस ने 'एल्टेरो कैफे 2.0' पर छापा मारकर संचालक यश कुमार को गिरफ्तार किया। यहां से 4 हुक्के, चिलम, पाइप और नशीले तंबाकू फ्लेवर के डिब्बे बरामद किए गए। मौके पर हुक्का पीते मिले 7 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस पूरे अभियान के दौरान 3 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम 2000 और कोटपा अधिनियम 2019 (संशोधित) की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले अवैध हुक्का बार संचालकों को खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।